अमृत वाणी

एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। न वह टूटता है और न उसमें रहने वाला कभी दुखी होता है।

-अज्ञात,

ऐसी दुर्दशा में कैसे हो पढ़ाई

शासन गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दे रही है। शिक्षकों पर दबाव बनाने के साथ-साथ उच्चाधिकारी समय-समय पर शालाओं का निरीक्षण कर रहे है, बच्चों की पढ़ाई का स्तर जांच रहे है लेकिन जहां मूल में ही कमियां हो, बुनियादी ढांचा जर्जर हो वहां गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की अपेक्षा कैसे की जा सकती है।

शहर से लेकर गांवों तक अगर शासकीय स्कूल भवनों की हालत पर नजर डालें तो यह स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। अधिकतर शाला भवनों की हालत इतनी जर्जर है कि वहां शाला का संचालन ही काफी मुश्किल होता है। जैसे-तैसे शिक्षक और बच्चे वहां अपनी पढ़ाई को जारी रखने का प्रयास करते हैं। वर्षाकाल में हालात और भी खराब हो जाते हैं। खुले में बैठकर पढ़ाई संभव नहीं होती और कमरों में इतना पानी टपकता है कि वहां बैठना संभव नहीं होता। अतः कही एक कमरे में तीन क्लास तो कही दो कमरो में पांच कक्षाएं लगाकर काम चलाया जाता है।

कुछ भवनों की हालत तो इतनी भयावह है कि वहां बच्चों और शिक्षकों का होना खतरे से खाली नहीं। दीवारों में दरार, जर्जर छत से प्लास्टर गिरना जैसे हालात में हर क्षण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ऐसे में कहां से लाए एकाग्रता और कैसे करें पढ़ाई। गुणात्मकता तो दूर की बात है।

बस्तर विकासखंड के ग्राम बड़े आमावाल में स्थित पूर्व माध्यमिक शाला का साक्षात उदाहरण आंखों के सामने है। इस स्कूल की दीवार और छत बुरी तरह जर्जर हो गई है। स्कूल लगने के दौरान छत और दीवार के प्लास्टर जिस तरह से गिर रहे है उससे कभी भी खतरा हो सकता है। यही नहीं स्कूल के सभी कमरों में छत से पानी टपक रहा है। बैठने की जगह भी नहीं है।

दरअसल एक तो शासकीय निर्माण कार्यों में आमतौर पर गुणवत्ता का सर्वथा अभाव होता है, उस पर निर्माणों के रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता जिससे कुछ ही समय में चाहे वे भवन हो या सड़क या फिर पुल पुलिया जर्जर होने लगते हैं।

बड़े आमावाल के उस स्कूल भवन की हालत पर ही गौर करें। सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2013 में इसका निर्माण किया गया था। पांच वर्षों में ही यह जिस हालत में पहुंच गया है उससे उसके निर्माण की गुणवत्ता और उसके पीछे की सांठ गांठ का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

केवल यही नहीं, स्कूल की जर्जर हालत के बारे में बकायदे संबंधित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को सूचित किए जाने के बावजूद किसी में अब तक उसकी सुध लेने की जरूरत ही नहीं समझी। मानो हर किसी को किसी दुर्घटना की प्रतीक्षा हो।

ग्रीष्मावकाश के बाद 16 जून से शालाएं खुलती हैं यानि मानसून के शुरूआत के साथ और फिर इस मौसम के चलते ही सितम्बर में बच्चों की तिमाही परीक्षाएं होती है। बच्चे एक ओर स्कूल में भींगते रहें और दूसरी ओर शालाओं में पढ़ाई का माहौल ही न हो तो वे कैसी पढ़ाई कर पाएंगे, कैसी परीक्षा देंगे और क्या होगा उसका स्तर यह सोचने का विषय है।

राज काज

माल्या बलि का बकरा

भारतीय बैंकों से करोड़ों का कर्ज लेकर फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या का कहना है कि उन्हें कांग्रेस और भाजपा ने फुटबॉल बना दिया और अब बलि का बकरा उन्हें बनाया जा रहा है। इसमें शक नहीं कि कोई भी करोड़ों का कर्ज यूं ही हासिल नहीं कर सकता, जब तक कि सरकारी नुमाइंदे इसमें शामिल न हों, लेकिन सवाल यह है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल क्योंकर किया जा रहा है। दरअसल जहां माल्या को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में लगी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ जानकार कह रहे हैं कि आम चुनाव से ठीक पहले माल्या और अन्य विदेश भागे कर्जदारों को यह सरकार भारत लाकर बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है। इसलिए माल्या कह रहे हैं कि उन्हें इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया है। अगर यह बात सही है तो फिर यह बहुत ही गिरी हुई राजनीति का हिस्सा है जहां अपराधियों को लगातार संरक्षण देने और उसके बाद चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए उनका इस्तेमाल करने का खेल खेला जा रहा है।

अब बुनियादी ढांचे का सवाल

यह तो सभी जान चुके हैं कि यूपीए ने 126 राफेल विमानों की खरीद के लिए फ्रांस से सौदा तय किया था, लेकिन एनडीए सरकार ने सिर्फ 36 राफेल ही खरीदे, वो भी बहुत ज्यादा कीमत पर आखिर क्यों इस सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि 36 से ज्यादा विमान रखने के लिए एयरफोर्स के पास बुनियादी ढांचा नहीं था। इस पर भी सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर सरकार बुनियादी ढांचा तैयार करने की बजाय ऐसे महंगे सौदे विदेशों से क्योंकर कर रही है, जबकि उसकी उपयोगिता पर ही सवाल उठ रहे हैं और वह भी कोई और नहीं बल्कि खुद रक्षा मंत्री उठा रही हैं। इसके लिए तो जरुरी यह होता कि मोदी सरकार यह पैसा अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उसके प्रसार पर लगाती तो बेहतर होता, कम से कम इस राजनीतिक उठा.पटक से तो बच रहते और काम भी पुख्ता हो जाता।

जब इंडियन अयूब ने दी पाक अयूब को मात

आज पुण्य तिथि पर विशेष

वर्ष 1965 के भारत.पाक युद्ध को दोनों सेनाओं के टैंकों की लड़ाइयों के लिए भी याद किया जाता है। उस समय पाकिस्तान को अपने पैटन टैंकों पर बहुत घमंड था जो उसे अमेरिका से मिले थे। उनके लिए पाकिस्तानी जनरल कहा करते थे कि इन टैंकों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है ये तो अजेय हैं। उस युद्ध में भारतीय सेना के रिसालदार अयूब खान ने पाकिस्तान के इन्हीं 4 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर उनका घमण्ड तोड़ दिया था। इस कारनामे के बाद वे अखबारों के माध्यम से देश में इंडियन अयूब के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस नाम के प्रसिद्ध होने की एक दिलचस्प वजह और थी। उस समय पाकिस्तानी के राष्ट्रपति व सेनाध्यक्ष का नाम भी जनरल अयूब खान था जिसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था। इसलिए अखबारों में बहुत लिखा गया कि पाकिस्तानी अयूब खान के मुबाकले भारत के पास भी एक अयूब खान है जो पाकिस्तान के पैटन टैंकों को मिट्टी में मिला सकता है।

पाकिस्तानी फौज का नाको चने चबा देने पर कैप्टन अयूब खान की बहादुरी के चर्चे पाकिस्तान में भी होते थे। पाकिस्तान की फौज अपने जनरल अयूब के नेतृत्व पर नाज करती थी। तब भारतीय फौज कहा करती थी कि पाकिस्तानी जनरल को युद्ध में घुटने टिकवा देने के लिए हमारे इंडियन अयूब ही काफी हैं। इससे पूर्व कैप्टन अयूब खान 1962 के युद्ध में भी भाग ले चूके थे।

भारत. पाक युद्ध में 9 सितम्बर 1965 को अयूब खान ने सुचेतगढ़ क्षेत्र में पाकिस्तानी टैंकों से टकराते हुए अपने टैंक को दुश्मन के कई टैंको के बीच ले गए और ताबड़तोड़ तरीके से खिलौने की तरह पाकिस्तान के 4 टैंकों को अपने निशाने से तोड़ा तो पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मच गई और उनके हौसले पस्त हो गए। युद्ध के दौरान कैप्टन अयूब खान द्वारा कब्जाये गए पाकिस्तानी टैंकों में से एक पैटन टैंक भी भारतीय अयूब अपने साथ लाए थे जिसे जम्मू में रखा गया था।

उत्तर पंजाब का असल वह सरहदी इलाका है जो पाकिस्तानी पैटन टैंकों की कब्रगाह बना। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यहीं सबसे भीषण मुठभेड़ हुई। यहीं से जनरल हरबक्श सिंह ने पाकिस्तानी सीमा में घुसने का प्लान बनाया था। इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तानी सीमा में पड़ने वाली इच्चोगिल नहर को तहस नहस किया जाना था। खबर थी कि लाहौर के पास वाले शहर कसूर और खेमकरन सेक्टर से होकर ही पाकिस्तान के पैटन टैंक भी हिंदुस्तान में घुसेंगे। यह वही कसूर शहर है जिसके बारे में कहते हैं कि उसे राम के बेटे कुश ने बसाया था जहां मशहूर गायिका नूरजहां पैदा हुई थी।

भारत.पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान के पैटन टैंक तोड़ने वाले रिसालदार मोहम्मद अयूब खान को युद्ध में किये गये उनके बहादुरी के प्रदर्शन के लिये भारत सरकार द्वारा 14 नवम्बर 1965 को उन्हे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉण् सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने वीर चक्र से सम्मानित किया था। उस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हम पाकिस्तान के जनरल अयूब खान से तो नहीं मिले लेकिन हमें अपने रिसालदार अयूब खान पर गर्व है। कैप्टन अयूब खान की बहादुरी को रेलवे ने भी सम्मान देते हुए उनके पैतृक गांव नूआं के रेलवे स्टेशन पर एक वार मेमोरियल स्टोन स्थापित किया। यह शिलालेख आज भी रेलवे स्टेशन के मुख्य भवन में लगा हुआ कैप्टन अयूब खान की बहादुरी की याद दिला रहा है।

कैप्टन अयूब खान का जन्म 1932 में राजस्थान के झुंझुनू जिले के नूआं गांव में हुआ था। उनके पिता इमाम अली खान किसान थे। माता का नाम मिमन था। वे चार भाइयों में सबसे बड़े थे। कैप्टन अयूब खान के परिवार में उनकी पत्नी ताज बानो, बेटी नसीम बानो, नसरीन बानो, पुत्रवधू शबनम खान,पोता आदिल खान है। उनके दत्तक पुत्र सलाउद्दीन का कुछ समय पहले इंतकाल हो चुका है।

जून 1950 में अयूब खान 18 कैवेलरी में भर्ती हुए थे। अयूब खान 1982 में सेना की 86 आमर्ड से ओनरेरी कैप्टन पद से रिटायर हुये थे। अयूब खान के दादाजी, पिताजी भी भारतीय सेना में काम कर चुके हैं। अब उनके परिवार के चचेरे भाइयों व उनके बच्चे सेना में काम कर रहे हैं। कैप्टन अयूब खान के परिवार की पांचवीं पीढ़ी अभी सेना में कार्यरत है। नूआ गांव देश का एकमात्र ऐसा गांव होगा जिसके हर घर का एक.दो सदस्य सेना में जरूर कार्यरत मिलेगा। कैप्टन अयूब खान राजस्थान से एकमात्र मुस्लिम नेता थे जिन्होने दो बार लोकसभा सदस्य का चुनाव जीता।

1984 में कैप्टन अयूब खान कांग्रेस टिकट पर झुंझुनू से लाकसभा चुनाव लड़ा व विजयी हुये। 1991 में वे दूसरी बार लोकसभा चुनाव में विजयी हुये थे। कैप्टन अयूब खान वर्ष 1995 में नरसिम्हा राव सरकार में केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाए गए। उन्होने कांग्रेस पार्टी में प्रदेश स्तर पर कई वरिष्ठ पदो पर काम किया। 15 सितम्बर 2016 को कैप्टन अयूब खान का 84 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। लोगो ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी।

साधारण परिवार में जन्मे अयूब खान में देश भक्ति का जज्बा कूट कूटकर भरा हुआ था। सेना से संसद तक पहुंचे कैप्टन अयूब खान अपने गांव में ही रहते थे। वे गांव के छोटे बच्चें को बुलाकर उसको देश सेवा का पाठ पढ़ाया करते थे। वे रोजाना खेतो में जाते थे। निधन से एक घंटे पूर्व भी वे खेत में जाकर उनको संभाल कर आए थे।

कैप्टन अयूब खान उस कायमखानी कौम से तालुक्क रखते हैं जिसकी देशभक्ति की मिसाल पूरे देश में दी जाती है। कायमखानियों द्वारा देश सेवा में किये गये योगदान को देखें तो देश को मुसलमानों पर गर्व महसूस होता है। सेना में भर्ती होना तो मानो कायमखानियों का शगल है। इसीलिये भारतीय सेना की ग्रिनेडीयर में 13 फीसदी व कैवेलेरी में 4 फीसदी स्थान कायमखानियों के लिये आरक्षित हैं। झुंझुनू जिले मे कायमखानी समाज में आज ऐसे अनेक परिवार मिल जायेंगें जिनकी लगातार पांच पीढियां सेना में कार्यरत हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध से लेकर अब तक अनको कायमखानी वीरो ने सेना में जंग लड़ते हुये शहादत देकर देश का नाम रोशन किया है। देश की आजादी के बाद भी सेना में रह कर देश की रक्षा करते हुये 13 कायमखानी जवानों ने अपना जीवन का बलिदान कर दिया जिसमें से सात जवान तो अकेले झुंझुनू जिले के धनूरी गांव के ही थे।

रमेश सर्राफधमोरा
(ये लेखक के अपने विचार है)

गंगा की सफाईः त्वरित निर्णय और तेज चाल जरूरी

भारतवासियों, विशेषतः हिन्दुओं के लिए पूज्य गंगा नदी की स्वच्छता, पावनता और गंगाजल की विशिष्टता सदैव बहुत महत्वपूर्ण रही है। यों, गंगा में प्रदूषण की अति के विरुद्ध अस्सी वाले दशक में व्यापक आक्रोश भड़का था और साधुसंत तक नाराज हो उठे थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसके लिए पहली बार बड़ी धनराशि जारी की थी। फिर डॉ. मनमोहन सिंह ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करके राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण भी गठित किया था। भारी भरकम धनराशि का खर्च दर्शाये जाने के बाद भी गंगा जस की तस रही और आज भी वैसी ही मलिन है।

गंगा पर नये सिरे से तब नया शोर हुआ, जब श्माँ गंगे के बुलावे का दावा करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी भाजपा प्रत्याशी के रूप में गंगा तटवर्ती तमाम शहरों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहर वाराणसी से चुनाव लड़ने जा पहुँचे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने गंगा की स्वच्छता के लिए पृथक मंत्रालय बनाया। सुश्री उमाभारती को सबका जिम्मा सौंपा और बाद में नितिन गडकरी को यह मंत्रालय सौंप दिया। लेकिन सवा चार साल में बातें बहुत हुईं, योजनाएं बहुत बनीं लेकिन गंगा अब भी वैसी ही प्रदूषित, वैसी ही अस्वच्छ है। हम पहले भी लिखते रहे हैं कि भारत को उन देशों से सलाह और सहयोग लेना चाहिए, जिनका अपने देश की नदियों को स्वच्छ बनाने में का रिकार्ड है।

अब यह नया घटनाक्रम है कि जर्मनी गंगा को साफ करने के प्रयासों के तहत भारत को 12 करोड़ यूरो का सस्ता कर्ज दे रहा है। इस राशि से उत्तराखण्ड में नालों के पानी का शोधन करने की संरचना तैयार की जाएगी। जर्मनी के प्रभारी राजदूत जैस्पर वियेक ने स्वयं ही यह जानकारी दी।

राजदूत वियेक के अनुसार इस परियोजना में करीब 360 किलोमीटर तक नालों की संरचना को बदलना व इसका विस्तार करना शामिल है। इसमें घरों को नाले से जोड़ना व करीब 1ण्50 करोड़ लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला जलशोधन संयंत्र बनाना भी शामिल है। इनके अलावा 13 पंपिंग स्टेशन बनाना भी इसका हिस्सा है।

जर्मन राजदूत वियेक कहते हैं इस परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी में गंदा पानी गिरने से रोकना और नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है। जर्मनी की विकास समर्पित एजेंसी जीआइजेड ने गंगा बुक तैयार की है, जो विद्यालय जाने वाले बच्चों को नदी के बारे में सूचित करने के लिए लक्षित है। डैन्यूब बुक की तर्ज पर गंगा बुक तैयार किया गया है। गंगा बुक में पौराणिक, सामाजिक.सांस्कृतिक सूचनाएं व नदी के आर्थिक महत्व की जानकारियां होंगी व इसमें प्रदूषण फैलाने से बचने जैसे नदी में प्लास्टिक फेंकने से बचना आदि का सुझाव दिया जाएगा। इसका लक्ष्य नदियों के प्रति लोगों का व्यवहार बदलना है। हमने उत्तराखण्ड के एक सरकारी विद्यालय में इसका प्रयोग किया है व इसे अब राज्यभर के विद्यालयों में दोहराने की योजना है।

यह एक अच्छी पहल है और हम इसका स्वागत करते हैं। हम मानते हैं कि गंगा को निर्मल बनाने में जनजागृति महत्वपूर्ण है। लेकिन सच यह है कि उत्तराखण्ड से आगे, विशेषतरू उत्तरप्रदेश के कानपुर पहुँचकर गंगा रसायनों से प्रदूषित होती है। टेनरीज का रसायन युक्त जहरीला पानी गंगा के पानी को भी जहरीला बना देता है। फिर उन तमाम राज्यों के शहरी अपशिष्ट और खेतों के रसायनों से गंगा और प्रदूषित होती जाती है। गंगा में गाह की समस्या बिहार में गम्भीर हो जाती है। इस बारे में रोकथाम के कुछ प्रयास हुए हैं, लेकिन वे अभी तक कारगर नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी बाधा तो बांधों और बैराजों के कारण गंगा के प्रवाह की अविरलता अवरुद्ध होने की है। पता नहीं इसका कोई विकल्प कब खोजा जायेगा।

अजित वर्मा
(ये लेखक के अपने विचार है)

फोन बैंकिंग से डूबे बैंक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय डाक भुगतान बैंक का उद्घाटन करते हुए डॉ मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए उसे बैंकों की खस्ताहाल के लिए जिम्मेबार ठहराया है। मोदी ने कहा कि ष्वह फोन बैंकिंग का दौर था, जिस किसी भी धन्ना सेठ को कर्ज चाहिए होता थाए वह नामदार व्यक्ति से फोन कराकर आसानी से कर्ज ले लेता था। इसी तरीके से मनमोहन सिंह सरकार के पहले छह सालों में उद्योगपतियों को दरियादिली से ऋण दिए गए। इसीलिए 2013.14 में ही एनपीए बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपए हो गया था, लेकिन इसे सरकार महज ढाई लाख करोड़ ही बताती रही। अब यह राशि करीब 12 लाख करोड़ हो गई है। माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों को इन्हीं के कार्यकाल में कर्ज दिया गया। हमारी सरकार ने एक भी डिफॉल्टर को कर्ज नहीं दिया। अलबत्ता हम 12 सबसे बड़े डिफॉल्टरों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही करने में लगे हैंष् मोदी की इस बात में दम है। वाकई संप्रग सरकार के दौर में कंपनियों और निजी शिक्षा संस्थानों के दबाव में आकर ऐसे उपाय किए गए, जिससे बैंकों में जमा धन आसानी से कर्ज के रूप में प्राप्त हो जाए। इसी व्यवस्था के दुष्परिणाम है कि आज देश की समूची बैंक प्रणाली एक बड़ी परीक्षा के दौर से गुजर रही है।

नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्र में काबिज होने के बाद से लगातार ये कोशिशें जारी हैं कि कानूनों में बदलाव लाकर विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोडों पर लगाम कसी जा सके और बड़ी कंपनियों से कर्ज वसूली में तेजी आए। देश के बैंकों में जमा पूंजी करीब 80 लाख करोड़ है। इसमें 75 प्रतिशत राशि छोटे बचतकर्ताओं और आम जनता की है। कायदे से तो इस पूंजी पर नियंत्रण सरकार का होना चाहिए, जिससे जरूरतमंद किसानों, शिक्षित बेरोजगारों और लघु व मंझोले उद्योगपतियों की पूंजीगत जरूरतें पूरी हो सकें। लेकिन दुर्भाग्य से यह राशि बड़े औद्योगिक घरानों के पास चली गई है और वे न इसे केवल दावे बैठे हैं, बल्कि गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। जबकि फसल उत्पादक किसान आत्महत्या कर रहा है। एनपीए पर पर्दा डाले रखने के उपाय इस हद तक हैं कि सुप्रीम कोट के कहने के बाबजूद भी सरकार ने उन लोगों के नाम नहीं बताये थे, जो बैंकों के सबसे बड़े कर्जदार थे। अब चूंकि सरकार खुद वैधानिक पहल कर रही है, तो उम्मीद की जा सकती है कि वह स्वयं उन 1129 कर्जदारों के नाम उजागर करेगी, जिनके बूते साढ़े नौ लाख करोड़ रुपए का कर्ज डूबंत खाते में पहुंचा है।

हालांकि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक के सख्त निर्देशों के चलते 70 कंपनियां कर्ज चुकाने की व्यवस्था में लगी हैं। ये कंपनियां ऐसे खरीदार भी तलाशने में लगी है, जो इन्हें खरीद लें। हालांकि इन्हें कर्ज चुकाने की 180 दिन की जो अवधि दी गई थी, वह 27 अगस्त को पूरी हो गई है। बावजूद ये कंपनियां कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं आई है। लिहाजा इन्होंने एक बार फिर समयसीमा बढ़ाने की मांग की है। ये कंपनियां वे हैं, जिन पर 2000 करोड़ रुपए या इससे अधिक का कर्ज है। यदि ये कर्ज नहीं चुका पाती हैं तो इनकी सूची नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी के पास भेजी जाएगी। जहां इनके विरुद्ध दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इनपर 3 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। सौ करोड़ से लेकर 1900 करोड़ बकाया कर्ज वाली कंपनियां तो अभी वसूली के दायरे में ही नहीं आई है। नियमों को ताक पर रखकर एक ही समूह की कंपनियों को कर्ज देने के दुष्परिणाम क्या निकलते हैं, ये तब सामने आएगा, जब कर्ज न चुका पाने की स्थिति में दिवालिया कंपनियों में तालाबंदी होगी। इस स्थिति से इनमें काम कर रहे कर्मचारियों के सामने आजीविका का संकट पैदा होगा घ् इनमें उत्पादन बंद होने से इनकी सहायक कंपनियां प्रभावित होंगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था को बड़ी हानि होगी। क्योंकि हम देख चुके हैं कि कर्ज वसूली की सख्ती के साथ ही माल्या और नीरव मोदी जैसे कारोबारी विदेश की राय पकड़ लेते है। जिन 12 डिफॉल्टर कंपनियों पर सख्ती बरती जाने की बात प्रधानमंत्री कर रहे है, उनसे भी लिए कर्ज की आधी धनराशि ही मिलने की उम्मीद है। इसी साल जून के अंत तक 32 मामलों का निराकरण हुआ है। इनसे कुल दावे की करीब 55 फीसदी धनराशि वसूली जाना ही संभव हुई है। इससे लगता है कि पूरा कर्ज वसूला जाना मुश्किल ही है।

अब नई जानकारियों के मुताबिक छोटे व्यापारियों, भवन एवं कारों के खरीददार और शिक्षा के लिए ऋण लेने वाले लोगों के भी एनपीए में बढ़त दर्ज की गई है। ऋण की सूचना देने वाली कंपनी क्रिफहाई मार्क ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि लघु एवं मझौले कर्जों में शिक्षा, आवास वाणिज्यिक वाहन एवं कारों पर दिए गए कर्ज की वापसी भी नहीं हो रही है। इनमें आवास के लिए दिए गए कर्ज की हिस्सेदारी 18.27 फीसदी है, लेकिन इस श्रेणी में सकल एनपीए 1.77 फीसदी है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 1.44 फीसदी था। शिक्षा ऋण की श्रेणी में एनपीए 6.13 प्रतिशत से बढ़कर 11 फीसदी हो गया है। वाणिज्यिक वाहन और निजि उपयोग के लिए ली गई कारों पर एनपीए 45 फीसदी बढ़ गया है। इन वाहनों के लिए कंपनियों के दबाव में जिस तरह से कर्ज दिए गए हैं, उसी अनुपात में प्रदुषण भी बढ़ा है। इस हकीकत से यह भी पता चलता है कि रिजर्व बैंक और सरकार ने कर्ज वसूली के जो भी उपाय किए है, उनके कारगर नतीजे फिलहाल नहीं निकले है।

इस तथ्य से सभी भलिभांति परिचित हैं कि बैंक और साहूकार की कमाई कर्ज दी गई धनराशि पर मिलने वाले सूद से होती है। यदि ऋणदाता ब्याज और मूलधन की किस्त दोनों ही चुकाना बंद कर दें तो बैंक के कारोबारी लक्ष्य कैसे पूरे होंगे। वाहन ऋण जहां बढ़ी वाहन और ऑटो पार्ट्स कंपनियों के दबाव में दिए गए, वहीं शिक्षा ऋण, शिक्षा माफियाओं के दबाव में दिए गए। शिक्षा का निजीकरण करने के बाद जिस तरह से देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ और देखते.देखते विश्व.विद्यालय और महाविद्यालय टापुओं की तरह खुलते चले गए, उनके आर्थिक पोषण के लिए जरूरी था कि ऐसे नीतिगत उपाय किए जाएं, जिससे सरकारी बैंक शिक्षा ऋण देने के लिए बाध्य हों। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए शिक्षा के लिए ऋण देने के उदारवादी उपाय किए गए। प्रबंधन और तकनीकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये कर्ज छात्रों का उदार शर्तों पर दिए गए। 2008 के बाद देश व दुनिया में जो आर्थिक मंदी आई, उसके चलते रोजगार का संकट पैदा हुआ और प्रबंधन व तकनीकि संस्थानों की हवा निकल गई। इस कारण एक तो अच्छे पैकेज के साथ नौकरियां मिलना बंद हो गई, दूसरे 2015-16 में प्रबंधन के 80 और 2017 में प्रबंधन और इंजिनियरिंग के 800 कॉलेज बंद होने की खबरें आई हैं। जब शिक्षा के ये संस्थान इस दुर्दशा को प्राप्त हो गए तो इनसे निकले छात्रों को अच्छा रोजगार मिलने और कर्ज पटाने की उम्मीद करना ही व्यर्थ है।

इस शिक्षा के सिक्के का यह एक पहलू यह है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि प्रबंधन और तकनीकि शिक्षा को दिए गए इन कर्जे में से 90 फीसदी कर्ज ऐसे अभिभावकों की संतानों को दिए गए हैं, जो चाहें तो आसानी से कर्ज पटा सकते हैं। दरअसल ये कर्ज देने तो उन वंचित एवं गरीब लोगों को थे, लेकिन बैंकों ने इन्हें इसलिए कर्ज नहीं दिए, क्योंकि इनकी आर्थिक हैसियत जानकर बैंक इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हुए कि इनके बच्चे कर्ज पटा पाएंगे। इसलिए ये कर्ज प्रशासनिक अधिकारियों, अन्य सरकारी कर्मचारियों, चिकित्सकों, अभियंताओं और बैंकों में चालू खाता रखने वाले व्यापारियों की संतानों को दिए गए हैं। पिछड़े, दलित और आदिवासी छात्रों को भी उन्हीं को शिक्षा ऋण मिला है, जिनके अभिभावक सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। इसलिए इन पर यदि सख्ती की जाए, तो इनमें से बढ़ी राशि वसूली जा सकती है।

प्रमोद भार्गव
(ये लेखक के अपने विचार है)